



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 28 मार्च, 2002/7 चैत्र, 1924

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 28 मार्च, 2002

संख्या 1-29/2002-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम, 140 के अन्तर्गत मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2002

(2002 का विधेयक संख्यांक-7) जो आज दिनांक 28 मार्च, 2002 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

अजय भण्डारी,

सचिव;

हि० प्र० विधान सभा।

2002 का विधेयक सख्यांक 7.

मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2002

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का 11) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्न-लिखित रूप में यह अधिनियमत हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन अधिनियम, 2002 है। संक्षिप्त न और प्रारम्भ

(2) यह अगस्त, 2002 के प्रथम दिवस से प्रवृत्त होगा।

(2000
का 11)

2. मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 की धारा 10 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक में “चार हजार” शब्दों के स्थान पर संशोधन। “पांच हजार” शब्द रखे जाएंगे। धारा 10

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमानतः प्रत्येक माननीय मन्त्री अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान या उसके स्थाई निवास स्थान पर स्थापित टेलीफोन के बारे में स्थानीय और बाह्य कालों पर व्यय के कारण अधिकतम चार हजार रुपए प्रतिमास की प्रतिपूर्ति के हकदार हैं। अब इस राशि को चार हजार रुपए से बढ़ाकर पांच हजार रुपए करने के लिए मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 की धारा 10 का संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है। अतः पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

.....मार्च, 2002.

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 के अधिनियमित किए जाने पर राजकोष से प्रतिवर्ष 2.76 लाख रुपए का अतिरिक्त आवर्ती व्यय करना पड़ेगा। क्योंकि प्रस्तावित संशोधन भावी प्रभाव का है, इस लिए कोई अनावर्ती व्यय नहीं होगा।

प्रस्तावोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(नस्ति संख्या जी0ए0डी0-सी0 (बी0 ए0) (4)-24/94-III)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2002 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 7 of 2002.

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS
(HIMACHAL PRADESH) AMENDMENT BILL, 2002

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Salaries and Allowances of Ministers
(Himachal Pradesh) Act, 2000 (Act No. 11 of 2000).*BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh
in the Fifty-third year of the Republic of India, as follows :—1. (1) This Act may be called the Salaries and Allowances of
Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Act, 2002.Short title
and com-
mencement.(2) It shall come into force on the first day of August,
2002.(11 of 2000) 2. In section 10 of the Salaries and Allowances of Ministers
(Himachal Pradesh) Act, 2000, in sub-section (1), in first proviso,
for the words "four thousand", the words "five thousand" shall
be substituted.Amend-
ment of
section-10.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present each Minister is entitled to reimburse maximum four thousand rupees per month on account of expenditure on local and outside calls in respect of the telephone installed at any place within his constituency or at his permanent place of residence. Now, it has been decided to amend section 10 of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 and to increase this amount from four thousand rupees to five thousand rupees. This has necessitated the amendment in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

SHIMLA :

The.....2002.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State exchequer, to the tune of Rs. 2.76 lakhs per annum. As the proposed amendment is prospective in effect there will be no non-recurring expenditure.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

Recommendations of the Governor under Article 207 of the Constitution of India

File No. GAD-C-(PA)-4-22/94-III

The Governor of Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Bill, 2002, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.